भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1449
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद-रोधी उपाय

†1449. श्री ई. तुकाराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रमुख आतंकवाद-रोधी उपायों, विशेषकर आसूचना क्षमता में वृद्धि, अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र, सीमा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण से संबंधित उपायों का ब्यौरा क्या है और घुसपैठ के प्रयासों, आतंकवादी घटनाओं में कमी और नेटवर्कों को निष्प्रभावी करने के संबंध में उनके उल्लेखनीय परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीमा-पार से समर्थन, ऑनलाइन कट्टरता, एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफार्मों और मानवरहित/निगरानी से बचा लेने वाली प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले उभरते आतंकवाद के जोखिमों की पहचान की है और यदि हां, तो इसके प्रमुख कारक और खतरे के आकलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का केंद्र प्रायोजित सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के लिए केन्द्रीय वित्तपोषित सहायता, आधुनिकीकरण कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी समावेशन पहलों, विशेष प्रशिक्षण या संसाधन सहायता को आरंभ करने, विस्तार करने या उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): पिछले दो वर्षों में, सरकार ने कई बड़े आतंकवाद-रोधी उपाय किए हैं, जिनमें आसूचना बढ़ोतरी, अंतर-संस्थान समन्वय, ऑनलाइन कट्टरपंथ और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभरते जोखिमों से निपटने और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे आतंकी जोखिम को कम करने के लिए केन्द्रीय और राज्य विधि-प्रवर्तन संस्थानों की क्षमता काफी सुदृढ़ हुई है। केन्द्रीय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1449, दिनांक 09.12.2025

संस्थानों और राज्य पुलिस के मध्य अंतर-संस्थान समन्वय से आतंकी मॉड्यूल के विरुद्ध सफल संयुक्त अभियान संभव हुए हैं, जो आतंकवाद के लिए भर्ती और वित्तपोषण में सम्मिलित हैं।

कुछ उपाय इस प्रकार हैं -

- ज़िला स्तर तक बेहतर 'मैक' (MAC: मल्टी-एजेंसी सेंटर) कनेक्टिविटी के माध्यम से समन्वय को सुदृढ़ किया गया है, जिससे हिंसक चरमपंथ, उभरती सुरक्षा चुनौतियों, क्रिप्टोकरेंसी, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकी-वित्तपोषण, जैविक जोखिम, फ़ेक इंडियन करेंसी नोट्स (FICN), साइबर समन्वय, इत्यादि पर अलग-अलग MAC फ़ोकस समूहों के विश्लेषणात्मक और भविष्यात्मक कार्यों में सुधार हुआ है।

- हार्डवेयर और नेटवर्क गति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से MAC एवं सब्सिडियरी MAC (SMAC) के मध्य स्थापित तंत्र का उन्नयन किया गया है। यह आसूचना के वास्तविक समय (Real Time) में विश्लेषण के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ML (मशीन लर्निंग) से सक्षम सॉफ्टवेयर की सहूलियत भी देता है।

- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID), आसूचना ब्यूरो (IB) और राज्य आतंकवाद-रोधी प्रकोष्ठ (ATS) जैसी संस्थाएं, जिन्हें मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) प्लेटफॉर्म से सहायता मिलती है, आसानी से डेटा साझा करने और विश्लेषण के लिए डिजिटल टूल्स का तेज़ी से इस्तेमाल कर रही हैं ।

- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के मामलों की जांच पर NIA की हैंडबुक, जिसे 2024 में सभी राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों में भेजा गया है, ने राज्यों / केंद्र शासित क्षेत्रों को आतंकवाद के अन्वेषण का मानकीकरण करने में मदद की है, और अभियोजन के परिणामों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- NIA ने एक 'नेशनल टेरर डेटाबेस फ्यूजन एंड विश्लेषण सेंटर (NTDFAC)' भी गठित किया है, जिसमें बिग-डेटा विश्लेषण क्षमता है, जिसे प्राथमिकता वाले फोरेंसिक विश्लेषण और साक्ष्यों के वैज्ञानिक एकत्रीकरण के लिए 'फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (DFSS)' के साथ बेहतर समन्वय से समर्थन मिला है।

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और राज्य पुलिस, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की सुचारू रूप से जांच कर रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, चार्जशीट हुई हैं और सज़ा हुई है।

- NATGRID के IT प्लेटफॉर्म पर एक 'ऑर्गनाइज़्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (OCND)' बनाया जा रहा है ताकि NIA और राज्य ATS के मध्य सुरक्षित डेटा साझा हो सके, साथ ही अद्यतित NATGRID टूल्स भी उपयोग किए जा रहे हैं। विशेष रूप से 'GANDIVA', मल्टी-सोर्स डेटा कलेक्शन और विश्लेषण को सहयोग प्रदान कर रहा है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1449, दिनांक 09.12.2025

- नियमित रूप से बहु-संस्थान क्षमता निर्माण कार्यक्रम, संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास और समन्वय बैठकों ने संस्थानों के मध्य वास्तविक-समय में जानकारी साझा करने और परिचालनिक तालमेल को काफी सुदृढ़ किया है।

- साथ ही, कुशल फोरेंसिक मानव-संसाधन विकसित करने और प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रभावी जांच के लिए आवश्यक तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में काफी वृद्धि हो सके।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद् (NSG) ने मल्टी-सिटी, मल्टी-टारगेट अभियानों को सहयोग प्रदान करने के लिए एक बड़े अधिदेश के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ अंतर-संस्थान समन्वय को सुदृढ़ किया है, जिसे अभ्यास के माध्यम से मान्य किया गया है; और क्षमता-निर्माण पहलों के अधीन अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अतिरिक्त, NSG ने प्रभावी आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के आतंकवाद-रोधी पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर कई MoU हस्ताक्षरित किये हैं।

- NSG ने काउंटर-टेरर, काउंटर-हाईजैक, जंगल में बंधकों को छुड़ाने और मेट्रो/रेल में दखल देने सम्बन्धी कई संयुक्त मॉक अभ्यास किये हैं, और 2024-2025 के दौरान अलग-अलग शहरों में काउंटर-हाईजैक ड्रिल भी की हैं।

- ऑनलाइन कट्टरता और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग को रोकने के लिए, सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 के अधीन, बड़ी संख्या में चरमपंथियों और कट्टरपंथियों से जुड़े URLs को ब्लॉक कर दिया गया है, साथ ही साइबर-पेट्रोलिंग और डिजिटल निगरानी के उपाय भी बढ़ा दिए गए हैं।

- बॉर्डर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बलों को ड्रोन, थर्मल इमेजर, नाइट-विज़न डिवाइस, सेंसर और आवश्यक रियल-टाइम रडार/ऑप्टिकल सिस्टम जैसी उन्नत निगरानी की प्रौद्योगिकियों से लैस किया गया है।

- भारत ने सीमावर्ती आतंकवाद से निपटने के लिए मित्र- देशों के साथ आसूचना साझाकरण भी बढाया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, बेहतर तारबंदी (फेंसिंग), तेज़ पेट्रोलिंग और ड्रोन तथा सेंसर के अधिकतम उपयोग से संवेदनशील सीमाओं पर सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। इन उपायों से घुसपैठ की कोशिशें कम हुई हैं, ड्रोन इंटरसेप्शन अधिक हुए हैं, और हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। समन्वित परिचालनों के माध्यम से कई आतंकी तंत्रों को खत्म किया गया है।

(ग): केंद्र सरकार ने सीएपीएफ, राज्य पुलिस, केंद्रीय और राज्य के संस्थानों के लिए कई आधुनिकीकरण और सहायता कार्यक्रमों को प्रस्तावित एवं विस्तारित किया है, जो निम्नानुसार हैं-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1449, दिनांक 09.12.2025

- पिछले कुछ वर्षों में, देश में फोरेंसिक के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनायें हैं, जिनकी कीमत ₹4,800 करोड़ से अधिक है।

- राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (SFSLs) के आधुनिकीकरण एवं अद्यतन के लिए 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग ₹233 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन प्रयासों से राज्यों को उन्नत DNA टेस्टिंग मशीनें, आधुनिक फोरेंसिक उपकरण और मोबाइल फोरेंसिक वैन खरीदने में सहायता मिली है, ताकि तेज़ी से, ऑन-साइट जांच हो सके और फोरेंसिक प्रतिक्रिया तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ सके।

- हमारी फोरेंसिक जांच की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जगहों पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयों (NFSUs) के ऑफ-कैंपस बनाकर, क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी है, ताकि फोरेंसिक जांच के लिए कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मौजूदा 7 CFSL के अतिरिक्त, 8 और CFSL बनाए जा रहे हैं।

- सरकार ने समय-समय पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और दूसरे केंद्रीय संस्थानों को अधिसंरचना विकसित करने तथा अन्य सहयोग हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग-अलग केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की आवश्यकताओं का आकलन किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने CAPFs के लिए पुलिस अधिसंरचना योजनाओं के अंतर्गत 2021 से 2025-26 तक ₹21,710 करोड़ का वित्तीय परिव्यय तय किया है।

- सरकार अलग-अलग राज्य सरकारों/केंद्र-शासित क्षेत्रों को केंद्रीय प्रायोजित उप-योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसे 'इंडिया रिज़र्व बटालियन/स्पेशलाइज़्ड इंडिया रिज़र्व बटालियन' के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए 2021 से 2025 के बीच ₹350 करोड़ का वित्तीय व्यय तय किया गया है।

- CAPFs और राज्य पुलिस फोर्स को नियमित रूप से आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें उन्हें बेहतर परिचालनिक संचार, प्रशिक्षण, पुलिस इकाइयों के सशस्त्रीकरण, चरमपंथी एवं कट्टर समूहों पर निगरानी रखने और जानकारी को बेहतर तरीके से साझा के लिए अंतर-संस्थान समन्वय के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों को प्रदान करना सम्मिलित है।

******